

47वाँ जी-7 शिखर सम्मेलन

प्रलिस के लयः

जी-7, COVAX कार्यक्रम, वशिव स्वास्थय संगठन

मेन्स के लयः

47वाँ जी-7 शिखर सम्मेलन एवं भारत और वशिव पर इसकी प्रतकिरयि

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 47वें जी-7 शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया।

- इससे पहले जी-7 देशों के वित्त मंत्री 'वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर' (GMCTR) की स्थापना करते हुए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुँचे थे।
- भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी "अतिथि देशों" के रूप में शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था।
- इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्रिटेन ने की। पछिला जी-7 शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में फ्रांस में हुआ था, पछिले वर्ष अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम को महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था।

'ग्रुप ऑफ सेवन' (जी-7)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है।
- जी-7 देश यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं।
 - सभी जी-7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
- जी-7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई नश्चिति मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिये गए नरिणय गैर-बाध्यकारी होते हैं।

प्रमुख बदिः

एक वशिव परयोजना के लयि बेहतर नरिमाण

- इसका उद्देश्य चीन के ट्रलियिन-डॉलर की 'बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर' पहल के साथ प्रतसिपर्द्धा करना है, जिसकी छोटे देशों पर असहनीय ऋण भार के चलते उन्हें परेशान करने के कारण व्यापक आलोचना की गई है, लेकिन वर्ष 2013 में लॉन्च होने के बाद से इसमें जी-7 सदस्य इटली भी शामिल है।
- यह सामूहिक रूप से नमिन और मध्यम आय वाले देशों (एशिया और अफ्रीका में) हेतु सैकड़ों अरबों के बुनियादी ढाँचे के नविश को उत्प्रेरति करेगा और जी-7 के साथ एक मूल्य-संचालित, उच्च-मानक और पारदर्शी साझेदारी की पेशकश करेगा।

डेमोक्रेसी 11:

- जी-7 और अतिथि देशों द्वारा "खुले समाज" को लेकर एक संयुक्त बयान (डेमोक्रेसी 11) पर हस्ताक्षर किये गए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु मूल्यों की पुष्टि और उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है और लोगों को भय और दमन से मुक्त रहने में मदद करता है।
 - यह बयान राजनीतिक रूप से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिये खतरों में से एक के रूप में भी संदर्भित करता है।

◦ जबकयिह बयान चीन और रूस पर नरिदेशति है, भारत जममू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतर्बिधों की जाँच कर रहा है।

- डेमोक्रेसी-11 को बढ़ते सत्तावाद, चुनावी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, आर्थिक जबरदस्ती, सूचनाओं में हेराफेरी, दुष्प्रचार, ऑनलाइन नुकसान और साइबर हमलों, राजनीति से प्रेरति इंटरनेट शटडाउन, मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग, आतंकवाद एवं हसिक उग्रवाद जैसे स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लयि खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

‘कार्बज़ि बे’ घोषणा:

- जी-7 ने ‘कार्बज़ि बे’ घोषणा पर हस्ताक्षर कयि। इसका उद्देश्य भवषिय की महामारयिों को रोकना है।
- जी-7 ने गरीब देशों को 1 बलियिन से अधिक कोरोनावायरस वैक्सीन खुराक देने का भी वादा कयि, जसिमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 मलियिन ब्रिटिन प्रदान करेगा।
 - वर्ष 2022 के मध्य तक दुनयिा की कम-से-कम 70% आबादी को टीका लगाने के लयि 11 अरब खुराक की आवश्यकता है।
- यह खुराक सीधे और अंतर्राष्ट्रीय COVAX कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

जलवायु परिवर्तन:

- गरीब देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करने के लयि प्रतर्विष 100 बलियिन अमेरिकी डॉलर की अतदिय व्यय प्रतर्जिज्ञा को पूरा करने हेतु योगदान को बढ़ाने की प्रतर्जिज्ञा को नवीनीकृत कयिा गया।
- वर्ष 2030 तक जैव वविधिता के नुकसान को रोकने और इसमें सुधार की प्रतर्बिद्धता ज़ाहरि की गई।
- वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचने का संकल्प लयिा गया।

चीन पर प्रतर्कियि:

- जी-7 का बयान जसि पर भारत और अन्य बाहरी देशों द्वारा हस्ताक्षर नहीं कयि गए थे, ने चीन पर झजियिांग (उइगर मुसलमि) और हॉन्गकॉन्ग में "मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता" तथा दक्षणि चीन सागर में यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों पर प्रहार कयिा।
- इसने चीन में एक पारदर्शी और समय पर वशि्व स्वास्थ्य संगठन से कोवडि के मूल का अध्ययन करने का भी आह्वान कयिा।
 - भारत ने भी वशि्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक बयान में ऐसा ही करने का आह्वान कयिा था।

भारत का पक्ष:

- सत्तावाद, आतंकवाद और हसिक उग्रवाद, दुष्प्रचार एवं आर्थिक दबाव से उत्पन्न खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा करने में भारत जी-7 देशों का एक स्वाभाविक सहयोगी है।
- भारत ने चतिा व्यक्त की कसिमाज वशिष रूप से दुष्प्रचार और साइबर हमलों की चपेट में है।
- इसने कोवडि -19 टीकों के लयि पेटेंट सुरक्षा के लयि समूह का समर्थन मांगा।
- ग्रह का वातावरण, जैव वविधिता और महासागरों की सुरक्षा के संबंध में काम करने वाले देशों द्वारा संरक्षति नहीं कयिा जा सकता है और जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्रवाई का आह्वान कयिा।
 - भारत एकमात्र जी-20 देश है जो अपनी पेरसि प्रतर्बिद्धताओं को पूरा करने की राह पर है।
- वकिसशील देशों को जलवायु वतित तक बेहतर पहुँच की आवश्यकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रतर् एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जसिमें शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकि हस्तांतरण, जलवायु वतितपोषण, इक्वटी, जलवायु न्याय और जीवन शैली में परिवर्तन शामिल हैं।
- आधार, प्रतयक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और JAM (जन धन-आधार- मोबाइल) ट्रनिटी जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से भारत में सामाजिक समावेश और सशक्तीकरण पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्रांतिकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस